उपरोक्त दोनों श्रेणियों के स्कूलों के लिए राज्य-वार कितनी प्रतिशत राशि दी गई है;

(ग) जून, 1991 से जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान स्कूलों के निर्माण और नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान भी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को धन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री) (कुमारी शैलजा) : (क) जवाहर रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक स्कूल योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक स्कूल भवनों की 48% लागत सरकार द्वारा मजदूरी लागत के रूप में प्रदान की जाती है।

(ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड में माध्यमिक स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। आबंटनों के राज्य-वार ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (**नीचे देखिए**)

(घ) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत राज्यों को वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक

प्रदान की गई राज्य-वार सहायता राशि का विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मुक्त की गई राशी (लाख रु0 में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	359.019
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.85
3.	असम	263.76
4.	गोवा	24.00
5.	गुजरात	1594.46
6.	हरियाणा	737.90
7.	हिमाचल प्रदेश	675.93
8.	जम्मू और कश्मीर	1323.60
9.	कर्नाटक	1475.14
10.	केरल	169.04
11.	महाराष्ट्र	302.81
12.	मेघालय	60.00
13.	मिजोरम	15.60
14.	उडीसा	2824.80
15.	पंजाब	729.70
16.	राजस्थान	33.13
17.	त्रिपुरा	61.01
18.	उत्तर प्रदेश	1112.40
19.	पश्चिम बंगाल	664.32

Modernisation of Museums

685. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether priceless artifacts and other ancient items are lying uncovered in Museums in the country; and

(b) if so, the steps proposed to be taken for improvement and modernisation of the Museums all over the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SEUA): (a) No, Sir, in so far as Museums under the control of Central Government arc concerned.

(b) Does not arise.

Modernisation of Rourkcla Steel Plant

686. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the first phase of the modernisation of Rourkela Steel Plant has been completed;

(b) if so, the amount spent on the modernisation of the first phase of the above Steel Plant;

(c) the target fixed for the modernisation of the second phase of that Steel Plant; and

(d) the steps taken in that direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Major production facilities for Phase-I of the Modernisation of Rourkela Steel Plant (RSP) of Steel Authority of India Limited (SAIL) have been completed in March, 1994.

(b) An expenditure of Rs. 503.35 crores has been incurred in Phase-I of the modernisation programme upto June, 1995.

(c) The target date of completion of Phase-II of the modernisation programme is August, 1996.

(d) For timely completion of Phase-II of the modernisation programme, SAIL (RSP) have taken the following measures:

(i) Providing construction equipment support to the contracting agencies.

(ii) Making direct payments to sub-vendors for critical equipment supply as well as for site activities.

(iii) Organising vendors/sub-vendors interaction to resolve their problems for timely equipment supply.

(iv) Maintaining buffer stock for cement and steel to ensure its timely availability to the contracting agencies, wherever needed,

(v) Taking over the jobs from the defaulting contracting agencies in cases of unsatisfactory performances and executing the same through alternate agencies.

(vi) Monitoring the project very closely at Plant/Corporate and Government levels.

गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र में कमी

687. **प्रो0 राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र में निरंतर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) गन्ने के अन्तर्गत जिला-वार क्षेत्र के संबंध में आंकड़े राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं।

Funding of mining projects by External Agencies

688. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether any external agencies have been funding the mining projects in the country;

(b) if so, the details of the funds made available during the last three years; and

(c) the progress made in implementing the projects and the extent of area covered, Projectwise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details of the funds made available during the last 3 years and progress made in implementing the projects are as follows: